



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 515]

No. 515]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 20, 2006/वैशाख 30, 1928

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 20, 2006/VAISAKHA 30, 1928

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2006

का.आ. 777(अ).— यतः दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम 2006 (2006 का 22) (यहाँ इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा-3 के निबन्धनों के अनुसार अप्राधिकृत विकास की श्रेणियों के संबंध में स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी सभी नोटिस, मई, 2006 के 19वें दिन अर्थात् जिस तारीख से उक्त अधिनियम प्रवृत्त हुआ, से एक वर्ष की अवधि के लिये निलम्बित माने जायेंगे;

और यतः उक्त अधिनियम की धारा-3 के उपबंधों के निबन्धनों के अनुसार जनवरी, 2006 के प्रथम दिन को यथा मौजूद, मास्टर प्लान से भिन्न मिश्रित भू-उपयोग के संबंध में परिसरों की सीलिंग और स्वीकृत योजनाओं, से परे निर्माण कार्यों को गिराने सहित दायिद्विक कार्रवाई मई, 2006 के 19वें दिन से एक वर्ष के लिये निलम्बित रखी जायेगी।

अतः अब दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम 2006 (2006 का 22) की धारा-5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए स्थानीय प्राधिकरणों को एतद्वारा निम्नलिखित निर्देश देती है:

निर्देश

(1) किसी भी न्यायालय के निर्णय, आदेश अथवा डिक्री के अनुपालन में किसी भी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जनवरी, 2006 के प्रथम दिन के बाद सीलबंद किए गए परिसर मई, 2006 के 19वें दिन से एक वर्ष की अवधि के लिये जनवरी, 2006 के प्रथम दिन को प्रवृत्त स्थिति के अनुसार बहाल किए जाने के पात्र होंगे।

(2) सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, जिन्हें जून, 2006 के 30वें दिन तक अपने परिसरों में वाणिज्यिक कार्यकलाप बन्द करना अपेक्षित है, मई, 2006 के 19वें दिन से एक वर्ष की अवधि के लिए अपने परिसरों में जनवरी, 2006 के प्रथम दिन की स्थिति के अनुसार ऐसे कार्यकलाप जारी रख सकेंगे।

(3) मई, 2006 के 19वें दिन से एक वर्ष की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा-4 में यथा निर्दिष्ट अप्राधिकृत विकास की श्रेणियों के संबंध में स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा संगत विधियों के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी और की गई कार्रवाई की मासिक रिपोर्ट आगामी माह के प्रथम सप्ताह के अन्त तक सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजी जायेगी।

[फा. सं. के-12016/2/2006-डीडीआईबी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2006

S.O. 777(E).— WHEREAS in terms of section 3 of the Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2006 (22 of 2006) (hereafter referred to as the said Act), all notices issued by the local authorities in respect of the categories of unauthorized development, shall be deemed to have been suspended for a period of one year with effect from the 19th day of May, 2006 that is the date on which the said Act came into force;

AND WHEREAS in terms of the provisions of section 3 of the said Act, punitive action, including sealing of premises in respect of mixed land use not conforming to the Master Plan and demolition of construction beyond sanctioned plans, as existed on the 1st day of January, 2006, shall be suspended for a period of one year with effect from the 19th day of May, 2006;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2006 (22 of 2006), the Central Government hereby issues the following directions to the local authorities to give effect to the provisions of the said Act, namely:-

DIRECTIONS

(1) The premises sealed by any local authority in pursuance of a judgment, order or decree of any court after the 1st day of January, 2006, shall be eligible to be restored, for a period of one year, with effect from the 19th day of May, 2006, to the position as was obtaining as on 1st day of January, 2006.

(2) All commercial establishments which are required to cease carrying out commercial activities at their premises by the 30th day of June, 2006, may continue such activities at such premises, as they were being carried out on the 1st day of January, 2006, for a period of one year, with effect from the 19th day of May, 2006.

(3) During the period of one year, with effect from the 19th day of May, 2006, action as per relevant laws shall continue to be taken by the local authorities in respect of the categories of unauthorized development, as specified in section 4 of the said Act and a monthly report of the action taken shall be sent to the Secretary, Ministry of Urban Development, New Delhi by the end of the first week of the succeeding month.

[F.No. K-12016/2/2006-DDIB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.